



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17—मार्च 23, 2007 (फाल्गुन 26, 1928)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17—MARCH 23, 2007 (PHALGUNA 26, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 1 मार्च 2007.

बैंपवि. सं. आरईटी. बीसी. 61/12.01.001/2006-07—यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से 22 जून 2006 की अधिसूचना बैंपवि. सं. 90/12.01.001/2005-06 वापस ले ली जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट छूट की शर्त के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत का सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने की अपेक्षा बहाल की जाती है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं का 17 फरवरी 2007 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 5.75 प्रतिशत और 3 मार्च 2007 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 6.00 प्रतिशत का आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना जारी रखेगा, जैसा कि 14 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. बैंपवि. आरईटी. बीसी. 57/12.01.001/2006-07 में प्रावधान किया गया है।

आनन्द सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

संदर्भ : बैंपवि. सं. आरईटी. बीसी. 63/12.01.001/2006-07—यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से 22 जून 2006 की अधिसूचना बैंपवि. सं. बीसी. 92/12.01.001/2005-06 वापस ले ली जाए। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतद्वारा 22 जून 2006 से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को निम्नलिखित देयताओं के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने से छूट जारी रखने का निर्णय लिया है:—

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत की गयी गणना के अनुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं;
- (ii) एसीयू (अमरीकी डालर) खातों में जमा शेष;
- (iii) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ संपार्श्विकृत उधार लेने और ऋण देने के दायित्व (सीबीएलओ) संबंधी लेनदेन; और
- (iv) उनकी अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) के संबंध में मांग और मीयादी देयताएं।

तथापि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं के संबंध में रखा जाने वाला प्रभावी सीआरआर कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

आनन्द सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

मुंबई, दिनांक 9 मार्च 2007

बैं.प.वि. एआरएस सं. 12105/08.21.002/2006-2007--- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित लेखा परीक्षा फर्मों को वर्ष 2006-2007 के लिए तथा भारतीय स्टेट बैंक की अगली वार्षिक साधारण बैठक होने तक बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है :--

- (1) मैसर्स डी. पी. सेन एंड कंपनी, कोलकाता
- (2) मैसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, मुंबई

- (3) मैसर्स एस. के. मिश्र एंड कंपनी, नई दिल्ली
- (4) मैसर्स आर. जी. एन. प्राइस एंड कंपनी, चेन्नई
- (5) मैसर्स एम. एम. निसीम एंड कंपनी, मुंबई
- (6) मैसर्स जैन कपिला असोसिएट्स, दिल्ली
- (7) मैसर्स विनय कुमार एंड कंपनी, इलाहाबाद
- (8) मैसर्स एम. चौधरी एंड कंपनी, कोलकाता
- (9) मैसर्स लक्ष्मीनिवास एंड जैन, हैदराबाद
- (10) मैसर्स दत्ता सिंगला एंड कंपनी, दिल्ली
- (11) मैसर्स जी. एम. कपाडिया एंड कंपनी, मुंबई
- (12) मैसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, कोलकाता
- (13) मैसर्स वर्धमान एंड कंपनी, चेन्नई

जे. आर. पी. रत्नारव
मुख्य महा प्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 1st March 2007

DBOD. No. Ret. BC. 61/12.01.001/2006-07.—It has been decided to withdraw the notification DBOD. No. BC. 90/12.01.001/2005-2006 dated June 22, 2006 with immediate effect. Accordingly the statutory minimum Cash Reserve Ratio (CRR) requirement of 3 per cent subject to the exemptions specified by Reserve Bank of India from time to time of the total demand and time liabilities in respect of Scheduled Commercial Banks stands reinstated. Further in exercise of the powers conferred under the sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India hereby notifies that every Scheduled Commercial Bank should continue to maintain a Cash Reserve Ratio of 5.75 per cent effective fortnight beginning from February 17, 2007 and 6.00 per cent effective from the fortnight beginning from March 3, 2007 of its total demand and time liabilities as envisaged in Notification No. DBOD. Ret. BC. 57/12.01.001/2006-2007 dated February 14, 2007.

ANAND SINHA
Executive Director

DBOD. No. Ret. BC. 63/12.01.001/2006-07.—It has been decided to withdraw the notification DBOD. No. BC. 92/12.01.001/2005-2006 dated June 22, 2006 with immediate effect. In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India has however, decided to continue to exempt every Scheduled Commercial Bank from the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) on the following liabilities with effect from June 22, 2006:

- (i) Liabilities to the banking system in India as computed under Clause (d) of the explanation to sub-section (1) of Section 42 of the RBI Act, 1934;
- (ii) Credit balances in ACU (US\$) accounts;
- (iii) Transactions in Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) with Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL); and

(iv) Demand and Time Liabilities in respect of Offshore Banking Units (OBUs).

The effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total demand and time liabilities shall however, not be less than 3 per cent of the total demand and time liabilities.

ANAND SINHA
Executive Director

Mumbai, the 9th March 2007

Ref. DBS. ARS. No. 12105/08.21.002/2006-2007.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India Act, 1955 and in consultation with the Central Government, the Reserve Bank of India has appointed the following audit firms as Statutory Central Auditors of the State Bank of India for the year 2006-07 who shall hold office until the next Annual General Meeting of the bank :—

1. M/s. D. P. Sen & Co., Kolkata
2. M/s. Khandelwal Jain & Co., Mumbai
3. M/s. S. K. Mittal & Co., New Delhi
4. M/s. R.G.N. Price & Co., Chennai
5. M/s. M.M. Nissim & Co., Mumbai
6. M/s. Jain Kapila Associates, Delhi
7. M/s. Vinay Kumar & Co., Allahabad
8. M/s. M. Choudhury & Co., Kolkata
9. M/s. Laxminiwas & Jain., Hyderabad
10. M/s. Datta Singla & Co., Delhi
11. M/s. G. M. Kapadia & Co., Mumbai
12. M/s. Chaturvedi & Co., Kolkata
13. M/s. Vardhaman & Co., Chennai

J. R. P. RATNARAO
Chief General Manager